

### 29-03-2024

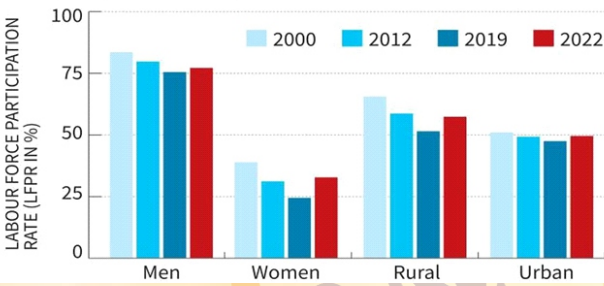
### भारत रोजगार रिपोर्ट 2024

#### सुखियों में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के युवा बढ़ती बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं, लगभग 83 प्रतिशत बेरोजगार आबादी इस जनसांख्यिकीय से संबंधित है।

#### Employment blues

Labour participation for various sections increased slightly in 2022 (compared to 2019) but was still low vis-a-vis 2000



#### संबंधित प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है जहां कुल बेरोजगार युवाओं में कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त शिक्षित युवाओं का अनुपात वर्ष 2000 में 35.2 प्रतिशत से लगभग दोगुना होकर 2022 में 65.7 प्रतिशत हो गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में बढ़ते नामांकन के बावजूद, गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं, स्कूल और उच्च शिक्षा स्तरों पर बच्चों में सीखने की कमी देखी गई है।
- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2000 और 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्परोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन COVID-19 महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट देखी गई। हालाँकि, शिक्षित युवाओं ने इस अवधि के दौरान काफी उच्च स्तर की बेरोजगारी का अनुभव किया।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), और बेरोजगारी दर (UR) में वर्ष 2000 और 2018 के बीच निरंतर गिरावट देखी गई, केवल वर्ष 2019 के बाद सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

- मजदूरी काफी हद तक स्थिर रही है या गिरावट आई है, नियमित श्रमिकों और स्व-रोजगार व्यक्तियों के लिए वास्तविक मजदूरी में 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अकुशल आकस्मिक श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को 2022 में अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली।
- विभिन्न राज्यों में रोजगार परिणामों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं, कुछ राज्य रोजगार संकेतकों में लगातार निचले स्थान पर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछले कुछ वर्षों में खराब रोजगार परिणामों से जूझ रहे हैं, जो क्षेत्रीय नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है।
- समग्र श्रम बाजार संकेतकों की प्रवृत्ति महिला श्रम बाजार में अधिक प्रमुखता से प्रतिध्वनित होती है। पिछले वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, महिला श्रम बाजार भागीदारी दर ने 2019 के बाद से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से ऊपर की ओर प्रक्षेपक प्रदर्शित किया।
- कृषि रोजगार से दूर जाने की धीमी गति में 2019 के बाद उलटफेर देखा गया, कृषि रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और गैर-कृषि रोजगार में गिरावट आई, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में।
- रिपोर्ट व्यापक आजीविका असुरक्षाओं को रेखांकित करती है, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो सामाजिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- शहरीकरण और प्रवासन दरों में वृद्धि का अनुमान है, अनुमान के अनुसार 2030 तक प्रवासन दर लगभग 40 प्रतिशत होगी और प्रवासन के कारण पर्याप्त शहरी जनसंख्या वृद्धि होगी, विशेष रूप से पूर्वी और मध्य क्षेत्रों से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में।
- रिपोर्ट महिला श्रम बल भागीदारी की कम दर के साथ श्रम बाजार में बढ़ते लिंग अंतर पर भी प्रकाश डालती है। युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को रोजगार हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियों के बावजूद सामाजिक असमानताएँ भी बनी हुई हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना

पड़ रहा है। यद्यपि सभी समूहों में शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है, सामाजिक पदानुक्रम कायम है, जिससे रोजगार असमानता बढ़ गई है।

### फाइनेंसिंग एग्रीकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (FARM)

#### सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में फाइनेंसिंग एग्रीकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में इकाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने भाग लिया।
- गौरतलब है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित, कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से यूएनईपी द्वारा किया जाता है।

#### FARM के बारे में

- फाइनेंसिंग एग्रीकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (FARM) एग्रीकेमिकल प्रदूषण से निपटने के लिए \$379 मिलियन बजट के साथ पांच साल की पहल है।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से वित्तीय सहायता के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में फाइनेंसिंग एग्रीकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, बैंकों और नीति-निर्माताओं के लिए व्यावसायिक मामले को फिर से तैयार करने के लिए विस्तार से बताता है। किसानों के प्रति नीति और वित्तीय संसाधन को सुलभ बनाता है, ताकि उन्हें जहरीले कृषि रसायनों के लिए कम और गैर-रासायनिक विकल्प अपनाने में मदद मिल सके और बेहतर प्रथाओं की ओर बदलाव की सुविधा मिल सके।
- पांच साल के कार्यक्रम में 51,000 टन से अधिक खतरनाक कीटनाशकों और 20,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को निकालने से रोकने का अनुमान है, जबकि 35,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने और 30 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को क्षरण से बचाने का अनुमान है। खेतों और किसानों के लिए कम-रासायनिक और गैर-रासायनिक विकल्प प्रदान करता है।
- एफएआरएम कार्यक्रम प्रभावी कीट नियंत्रण, उत्पादन विकल्पों और स्थायी उपज में व्यापार की उपलब्धता में सुधार के लिए बैंकिंग, बीमा और निवेश मानदंडों को मजबूत करते हुए पीओपी युक्त कृषि रसायनों और कृषि-प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और बेहतर प्रबंधन मानकों को अपनाने के लिए सरकारी विनियमन का समर्थन करेगा।

- FARM कार्यक्रम के उद्घाटन में सभी सात देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी बैंकों, नीति निर्माताओं, किसान सहकारी समितियों, खुदरा विक्रेता, कृषि रसायन और प्लास्टिक निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और कार्यक्रम में सीधे तौर पर शामिल 100 से अधिक भागीदार और हितधारक शामिल थे।
- यह कार्यक्रम कृषि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, किसानों और निर्माताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो अधिक न्यायसंगत और लचीली खाद्य प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करता है।

### कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC)

#### सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) का उद्घाटन किया। यह कृषि क्षेत्र में डिजिटल नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले एक व्यापक डैशबोर्ड के रूप में कार्य करता है, जो कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देता है।



#### ICCC के बारे में

- ICCC एक तकनीक-आधारित समाधान है जिसमें कई आईटी एप्लिकेशन और प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिसे सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में स्थित है, जो कृषि क्षेत्र में कानून, नीति निर्माण और पहल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- आईसीसीसी तापमान, वर्षा, हवा की गति, फसल की पैदावार और उत्पादन अनुमानों पर बड़ी मात्रा में दानेदार डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के



लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है और प्रस्तुत करता है। यह ग्राफिकल प्रारूप में है।

- ICCC रिमोट सेंसिंग सहित कई स्रोतों से प्राप्त भू-स्थानिक जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र की व्यापक निगरानी को सक्षम करेगा। यह मृदा सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्लॉट-स्तरीय डेटा; भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मौसम डेटा; डिजिटल फसल सर्वेक्षण से बुआई डेटा; कृषि मैपर से किसान और खेत से संबंधित डेटा, भूमि की जियो-फेंसिंग और जियो-टैगिंग के लिए एक एप्लिकेशन; कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) से बाजार खुफिया जानकारी; और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) से उपज अनुमान डेटा उपलब्ध कराएगा।
- डेटा का एकीकृत विजुअलाइज़ेशन ICCC पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा त्वरित और कुशल निर्णय लेने में सक्षम होगा, जिसे आगे चलकर पीएम-किसान चैटबॉट के साथ जोड़ा जा सकता है।

#### ICCC के व्यावहारिक अनुप्रयोग :

- किसान सलाह : मिट्टी के स्वास्थ्य, मौसम डेटा और फसल उपयुक्तता के आधार पर प्रामाणिक सलाह प्रदान करता है।
- सूखा कार्रवाई : सूखे के दौरान सक्रिय निर्णय लेने की सुविधा के लिए मौसम की स्थिति के साथ उपज में भिन्नता को सहसंबंधित करता है।
- फसल विविधीकरण : फसल विविधीकरण मानचित्रों के विश्लेषण के आधार पर विविध फसल के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करता है।
- फार्म डेटा रिपोर्टिंग : कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (के-डीएसएस) एक कृषि डेटा रिपोर्टिंग के रूप में कार्य करती है, जो साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और अनुकूलित सलाह देने में सहायता करती है।
- उपज का सत्यापन : कृषि मैपर के माध्यम से प्राप्त उपज डेटा की तुलना प्लॉट सत्यापन के लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के माध्यम से उत्पन्न डेटा से करता है।

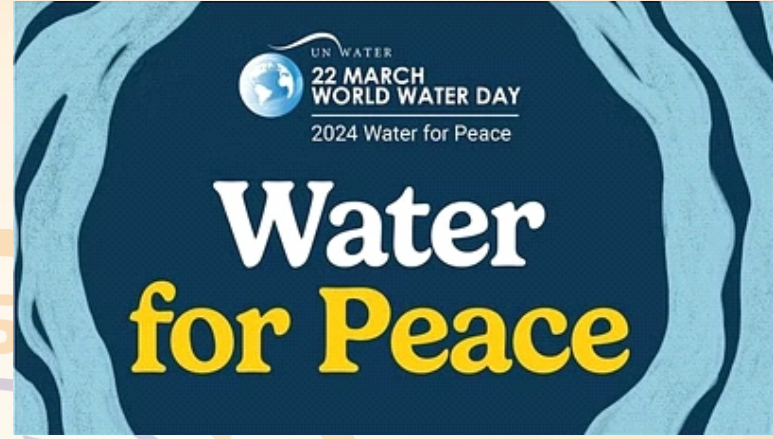
### विश्व जल दिवस 2024

#### सुर्खियों में क्यों?

- विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा मनाया जाता है जो मीठे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

#### संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष की थीम शांति के लिए जल है। इसका उद्देश्य उन तनावों को उजागर करना है जो पानी जैसे संसाधनों पर उभर सकते हैं, जिससे संभावित अस्थिरता और संघर्ष हो सकता है, लेकिन साथ ही शांति को बढ़ावा देने में पानी की क्या भूमिका हो सकती है, अगर सावधानी से प्रबंधित किया जाए।



- इस विश्व जल दिवस पर, हम सभी को पानी के लिए एकजुट होने और शांति के लिए पानी का उपयोग करने, एक अधिक स्थिर और समृद्ध कल की नींव रखने की जरूरत है।
- पानी शांति पैदा कर सकता है या संघर्ष भड़का सकता है। जब पानी दुर्लभ या प्रदूषित होता है, या जब लोग पानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, तो तनाव बढ़ सकता है। पानी पर सहयोग करके, हम हर किसी की पानी की जरूरतों को संतुलित कर सकते हैं और दुनिया को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।
- समृद्धि और शांति पानी पर निर्भर हैं। जैसे-जैसे राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, बड़े पैमाने पर प्रवासन और राजनीतिक अशांति का प्रबंधन करते हैं, उन्हें जल सहयोग को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखना चाहिए।
- पानी हमें संकट से बाहर निकाल सकता है। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों से लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई तक पानी के उचित और टिकाऊ उपयोग के लिए एकजुट होकर समुदायों और देशों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं।

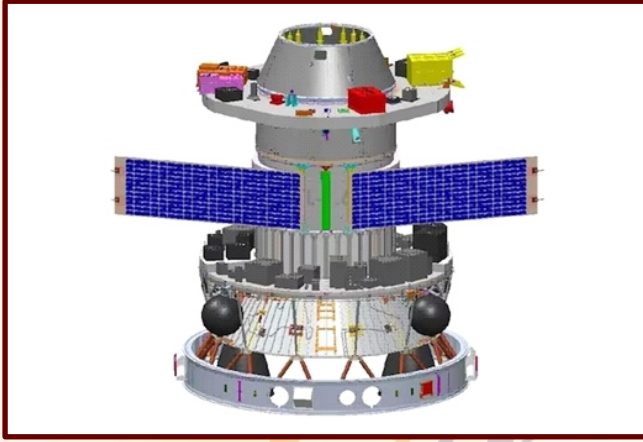
### PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 (POEM 3) मिशन

#### सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि उसका पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (पीओईएम-3) कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया।

## POEM-3 के बारे में

- POEM-3 को नव विकसित स्वदेशी प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए कुल 9 विभिन्न प्रयोगात्मक पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था।
- इनमें से छह पेलोड एनजीई द्वारा IN-SPACe के माध्यम से वितरित किए गए थे। इन पेलोड के मिशन उद्देश्य एक महीने में पूरे हो गए।



- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने पीएसएलवी के चौथे चरण को बढ़ाकर पीओईएम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- ऊपरी चरण की कक्षीय ऊंचाई प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में घटती रही, मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के साथ मॉड्यूल के 21 मार्च, 2024 को उत्तरी प्रशांत महासागर पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

- पीओईएम के माध्यम से, जो छोटी अवधि के अंतरिक्ष-जनित प्रयोगों को करने के लिए एक बहुत ही लागत प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है, इसरो ने अपने नए पेलोड के साथ प्रयोग करने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्टअप और एनजीई के लिए नए रास्ते खोले हैं।
- इस नवीन अवसर का उपयोग अंतरिक्ष में प्रयोग करने के लिए कई स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और एनजीई द्वारा प्रभावी ढंग से किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स, सैटेलाइट डिस्पेंसर और स्टार-ट्रैकिंग शामिल हैं।
- POEM में एकल-श्रृंखला कॉन्फ़िगरेशन में कुल एवियोनिक्स, मिशन प्रबंधन कंप्यूटर सहित एवियोनिक्स पैकेज में औद्योगिक-ग्रेड घटक, इलेक्ट्रिक पावर, टेलीमेट्री और टेलीकॉम के लिए मानक इंटरफेस और दर-जाइरो, सन सेंसर और मैग्नेटोमीटर का उपयोग करने वाले नए इन-ऑर्बिट नेविगेशन एल्गोरिदम जैसी नई सुविधाएं भी शामिल हैं।
- इसरो ने लागत-कुशल कक्षीय प्रयोग मंच की पेशकश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न बढ़ते खतरे को पहचानते हुए, विशेष रूप से कई छोटे उपग्रह समूहों के उद्भव के साथ, एजेसी ने उपग्रह प्रक्षेपण, मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों और अन्वेषण मिशनों सहित अंतरिक्ष संचालन के लिए महत्वपूर्ण खतरे पर जोर दिया।



**प्रयास**  
IAS ACADEMY

An Institute for UPSC & BPSC

f prayasiasacademy  
✉ prayasiasacademy  
🌐 prayasiasacademy.com

**ATTENTION**  
**UPSC / BPSC Aspirants**

**Boost your AIR with**

**GS TARGET COURSE**  
**FOR BPSC & UPSC**

हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM  
MODE: Offline & Online

ADMISSION OPEN  
upto **50%** OFF\*

